

खरीफ सीजन में यूरिया की हो रही कालाबाजारी स्वास्थ्य शिविर में इलाज के नाम पर ठगी

प्लाईवुड फैक्ट्री में गत्ते गलाने के लिए होता है इस्तेमाल

राहुल, ग्रेनो

संसद के विगत बजट सल में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए तो कई योजनाएं परोस दीं। लेकिन देश में अन्रदाताओं की स्थिति

धांधली

कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दादरी समेत दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में आज किसानों को धान में डालने के लिए सरकारी गोदाम से पर्याप्त यूरिया नहीं मिल रहा है। कारण यह है कि प्लाईवुड फैक्ट्री वालों को गत्ता व कूट को गलाने के लिए यूरिया की दरकार होती है और वे मुंह मांगी कीमत देने में समर्थ होते हैं, जिससे वे बाजार से सारा यूरिया खरीद लेते हैं। जब किसान सरकारी गोदामों पर



जाते हैं और वहां से उन्हें खाली हाथ वापस लौटा दिया जाता है। अगर एक-दो किसान को यूरिया

सरकारी दर से ज्यादा दाम वसूल रहे हैं दुकानदार

मिल भी जाता है, तो उन्हें उसके एवज में सरकारी दाम से ज्यादा

रुपया चुकाना पड़ता है। ज्ञात हो कि सरकारी कीमतों के अनुसार 45 किलो के पैकेट की कीमत 267 रुपये और 50 किलो के पैकेट की कीमत 296 रुपये तय की गई है। लेकिन काला-बाजारी के चलते किसानों को सरकारी दर पर यूरिया नहीं मिल पा रही है।

इस समस्या पर किसानों से बात करने पर पता चला कि उनसे प्रत्येक पैकेट पर बीस से पच्चीस रुपये ज्यादा वसूला जा रहा है। किसानों का कहना है कि हम लोगों के पास एक साथ इतनी रकम नहीं होती कि हम लोग एक बार में 10 से 20 पैकेट खरीद सकें। इसी का फायदा उठाकर प्लाईवुड कारखाने के लोग सरकारी गोदामों से पहले ही 15 से 20 रुपये अधिक दाम पर यूरिया खरीद लेते हैं और बाद में बाजार में अपनी कीमत लगाकर बेचते हैं। मनमाना दर लगाने के बाद बाजार में यूरिया खाद की एक पैकेट की कीमत 330 से लेकर 400 रुपये तक की आती है और हमें मजबूर होकर यूरिया खरीदना ही पड़ता है।

गौरव राय, नई दिल्ली

पिछले दो हफ्तों से न्यू अशोक नगर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करा रही हर्बल लाईफ संस्था पर ठगी का आरोप लग रहा है। शिविर में जांच के लिए जाने वाले लोगों को

आयोजक संस्था के खिलाफ कई मामले दर्ज

मामले की तपत्ती जारी

वहां मौजूद डॉक्टर पहले वजन कम करने, हृदय रोग, कुपोषण, मलेरिया, डेंगू जैसी बिमारियों के उपचार के बारे में बताते हैं। इसके बाद वे उन्हें निजी क्लीनिक सरपंच काम्पलेक्स में उपचार के लिए भेजते हैं, जहां मरीजों को कई तरह के जांच कराने के बाद महंगी दवाईयां दे दी जाती हैं। यहां के निवासी सोहन ने बताया कि वह बुधवार को शिविर में जांच के लिए गए थे। जांच के बाद उन्हें पेट से संबंधित समस्या बताई गई और लैब टेस्ट के लिए अशोक नगर स्थित न्यू



कैंप में लोगों की जांच करते हर्बललाइफ फ्री हेल्थ क्लब के सदस्य

हेल्थ क्लिनिक में जाने के लिए कहा गया। वहां पर टेस्ट और दवाईयों के नाम पर उनसे पैसे मांगें गए। उन्होंने पैसे देने से इंकार किया और बताया कि यहां तो सारी सेवाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। इस पर क्लीनिक संचालक ने कहा कि शिविर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। टेस्ट और हमारी फीस के पैसे अलग से लगते हैं और वो आपको देना ही होगा। सोहन ने इसकी शिकायत पास के थाने में दर्ज कराई है। इस गंभीर मामले पर जब पुलिस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इनके

खिलाफ कई शिकायत दर्ज की गई हैं। फिलहाल तपत्ती जारी है ठोस सबूत मिलने पर इनके उपर उचित कार्रवाई की जाएगी। संस्था से जुड़े हर्बललाइफ फ्री हेल्थ क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि हमारे उपर लगाये जाने वाले सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम तो लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य जांच सुविधा मुहैया करा रहे हैं। कई बार हमारे पास पैसे लोग आते हैं जिनकी हालत ऐसी होती है कि उनका इलाज यहां नहीं हो सकता। ऐसे में हमें उन्हें उपचार के लिए अन्य जगह भेजना पड़ता है और हम किसी के उपर दबाव भी नहीं डालते।

जीडीए के खिलाफ रेहड़ी-पटरी वालों का प्रदर्शन

सौन्दर्या द्विवेदी, इन्द्रापुरम

शहर में रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लोगों ने रेहड़ी-पटरी हटाये जाने के विरोध में जीडीए कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रश्न पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्द्रापुरम में लंबे समय से रेहड़ी लगाकर रोजगार चलाने वाले लोगों को जबरन हटाया जा रहा है। प्रशासन गरीबों की रोजी- रोटी



मनमानी के विरोध में अर्थारिटी का घेराव करते लोग

सामान नष्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जीडीए के प्रवक्ता ने बताया कि रेहड़ी-पटरी वाले मनमाने तरीके से सड़क और पटरियों पर फैंल जाते हैं। इसके चलते आवागमन में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में सड़क पर अक्सर जाम की समस्या बन जाती है। इस समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए ही जीडीए उपाध्यक्ष ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की घोषणा की थी। रेहड़ी-पटरी प्रदर्शनकारियों के रोष को देखते हुए जीडीए सचिव ने पांच तोड़-फोड़ करना शुरू कर देती है। दुकान में रखे गये सामनों को भी हटाने का मौका नहीं देती जिसके कारण हजारों रुपए का

कुमार का कहना है कि घर चलाने के लिए उसके पास और कोई और जरिया नहीं है। घर में तीन बेटियों को पालने और बीमार बीबी का इलाज भी इसी कमाई से होता है। ऐसे में प्राधिकरण रेहड़ी को हटा देगा तो उसके जैसे लोगों के परिवार का पेट कैसे भरेगा। गाज़ियाबाद शहर में कम से कम 10 अलग-अलग इलाकों में रेहड़ी-पटरी वाले दुकान लगाते हैं। इनको लेकर एक कानून भी बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि रेहड़ी को सड़को से हटाकर संरक्षित स्थान पर भेजने की बात कही गयी थी, लेकिन आजतक प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई पहल देखने को नहीं मिली।

राजधानी में बढ़ रहे हैं एटीएम फ्राँड के मामले

रितु गुप्ता, नई दिल्ली

राजधानी में एटीएम फ्राँड या बैंक खाते में सेंध लगाने के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर में रोजाना औसतन 100 से ज्यादा

धोखाधड़ी

एटीएम फ्राँड की शिकायतें आती हैं। बीते एक माह में दिल्ली के शकरपुर थाने में ही एटीएम ठगी के 300 मामले सामने आ चुके हैं। एटीएम

- **रोजाना होते हैं लगभग 100 एटीएम फ्राँड**
- **स्कीमर मशीन का इस्तेमाल करते हैं हैकर**

फ्राँड समेत आ इटी एक्ट की जानकारी रखने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या राजधानी में कम है जबकि शिकायतों की भरमार है। घटना लक्ष्मी नगर में रहने वाले गिरीश के खाते से रविवार को 15 हजार रुपये



निक्ल गए। ये ट्रांजेक्शन मंडावली के देना बैंक एटीएम से हुई थी। वह शकरपुर थाने में एफआइआर कराने पहुंचे तो वहां से उन्हें मंडावली थाने भेज दिया गया। मंडावली थाने ने भी एफआइआर करने से इंकार कर दिया। वह दोबारा शकरपुर थाने आए, बावजूद उनकी एफआइआर नहीं हुई। एटीएम ठगी के बढ़ते मामलों का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रविवार को पूर्वी दिल्ली स्थित शकरपुर थाने में देर तक एटीएम फ्राँड की शिकायत करने वालों की लंबी लाइन लगी रही। बता दें कि माल 4500

रुपये की स्कीमर मशीन की आड़ में हैकर एटीएम क्लोन करके करोड़ों रुपये चंपत कर लेते हैं। हैकर ज्यादातर देर रात जिस वक्त अमूमन लोग घरों में सो रहे होते हैं घटना को अंजाम देते हैं। सोते समय कहरा धारक को ट्रांजेक्शन का पता नहीं चलता। सुबह उठने पर उपभोक्ता को फ्राँड का पता लगता है और वह शिकायत करने पुलिस-थाने पहुंचता है। आईटी एक्ट का मामला होने के कारण पुलिस शिकायत दर्ज करने से यह कहर मुकर जाती है कि आइटी

एक्ट के मामलों की जांच इंसपेक्टर या सीनियर रैंक के अधिकारी ही कर सकते हैं। बावजूद अगर किसी तरह एफआइआर दर्ज हो जाती है तो भी रुपये मिलने या आरोपी के पकड़ने जाने की गारंटी शून्य होती है। इस तरह की 90 फीसद एफआइआर में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। इस तरह की ठगी का शिकार होने पर अगर पीड़ित बैंक से संपर्क करें तो भी उन्हें गुमराह किया जाता है। बैंक एफआइआर कराने को कहता है, क्योंकि उसे भी पता है कि आसानी से रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। अगर आपने एफआइआर कराले तो भी बैंक ये कहकर टाल देता है कि आपके पास पुलिस से कोई सूचना नहीं आई है। जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर बैंक को सूचना दे या उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट दे। ऐसे में पीड़ित जनता बैंक, पुलिस और कोर्ट के चक्कर ही काटती रह जाती है। सवाल यह उठता है कि आखिर जनता अपना रुपया कहा रखें।

बेटी पैदा होने की खबर सुन अस्पताल से भागे परिजन

अमानुल्लाह युसुफ, गाजियाबाद

सरकार देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने, पुरुषों के बराबर हक दिलाने के लिए तमाम प्रयास में लगी है।

शर्मनाक

मसलन बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना आदि लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। रोजाना बच्चियों, महिलाओं के खिलाफ ज्यादती का कोई न कोई मामला सामने आता है। ताज़ा घटना गाजियाबाद के मटियाला गांव के एक परिवार की है। बीते गुरुवार को गर्भवती महिला को परिजन नैन के सरकारी एम.एम.जी. अस्पताल में भरती कराया। परिवार को बेटा पैदा होने की आशा थी।



पीड़िता ने महिला-आयोग से मांगी मदद

कुछ घंटों बाद डिलीवरी रूम से बेटी पैदा होने की खबर मिली। बेटी का नाम सुनते ही सबके मुंह लटक गए। एक-एक कर परिजन अस्पताल से खिसकने लगे। अंत में जच्चा-बच्चा को अकेला छोड़कर पूरा परिवार

भाग गया। अस्पताल की नर्स सुनिता ने बताया कि महिला की शादी तीन साल पहले मटियाला गांव के युवक से हुई थी। सुसराल वाले शादी के बाद से ही महिला पर लड़का पैदा करने का दबाव बनाने लगे। लेकिन बीते गुरुवार को जब महिला को बेटी पैदा हुई और यह बात पति व सुसराल वालों को पता लगी तो वे वहां से

भाग गए। जब महिला को होश आया तो पति को पुकारने लगी तभी उसे अस्पताल की नर्स ने बताया कि बेटी पैदा होने की खबर मिलते ही उनके पति और सुसराल वाले तकरीबन दो घण्टे पहले ही यहां से जा चुके हैं। इसबात का पता लगते ही महिला चीखने-रोने लगी। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। उसके माँ-बाप ने महिला आयोग सदस्य निर्मला देवी से दुखड़ा सुनाया। निर्मला देवी ने परिवार वालों को पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की सलाह दी। मामला थाने में दर्ज करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना प्रभारी शिवम प्रधान ने बताया कि महिला को जल्द इंसाफ दिलाया जाएगा।

समूहगान प्रतियोगिता में सिद्धि विनायक स्कूल प्रथम

अभिषेक भारद्वाज, ग्रेनो

ग्रेटर नोएडा के दादरी में भारत विकास परिषद ने रविवार को राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिसमें की खबर मिलते ही उनके पति और सुसराल वाले तकरीबन दो घण्टे पहले ही यहां से जा चुके हैं। इसबात का पता लगते ही महिला चीखने-रोने लगी। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। उसके माँ-बाप ने महिला आयोग सदस्य निर्मला देवी से दुखड़ा सुनाया। निर्मला देवी ने परिवार वालों को पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की सलाह दी। मामला थाने में दर्ज करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना प्रभारी शिवम प्रधान ने बताया कि महिला को जल्द इंसाफ दिलाया जाएगा।



कार्यक्रम में सम्मानित हुए प्रतिभागियों का एक छायाचित्र

दादरी के सिद्धि विनायक पब्लिक स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरे और

- **अनुभवी शिक्षकों को किया गया सम्मानित**
- **अगली बार खेल सल का होगा आयोजन**

तीसरे स्थान पर क्रमशः दादरी पब्लिक स्कूल शैफाली पब्लिक स्कूल रहे।

परिषद ने सभी स्कूलों के अनुभवी शिक्षकों को भी सम्मानित किया। भारत विकास परिषद दादरी के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार शर्मा ने सबको प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और सभी छात्र-छात्राओं का उत्साह वर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत में हमारा संतान एक खेलों की प्रतियोगिता का भी आयोजन करायेंगा। जिसमें सभी छात्र-छात्राओं को भाग लेना का मौका मिलेगा।

आईआईएमटी में थिरके 'फलसफा' के सितारे

केतन चौहान, ग्रेनो

आईआईएमटी कॉलेज का माहौल आज खासा चहल पहल से भरा दिख रहा था। कॉलेज में आज हर ओर मस्ती का आलम था। मौका था 'फलसफा' फिल्म के प्रमोशन का। फलसफा फिल्म का प्रमोशन करने 'फलसफा' की सारी स्टारकास्ट और फिल्म के युवा निर्देशक हिमांशु यादव यहां पहुंचे थे। फिल्म के स्टार मनीत जौरा ने कहा कि यह फिल्म एक आम युवक और युवती की कहानी है यानी ठीक हमारी और आप की कहानी जैसी। जीवन में सभी से कोई न कोई गलती होती है। गलतियों से हम सबको सीख लेनी चाहिए और फिल्म का सन्देश यही है। 'फलसफा' की स्टारकास्ट टीम जैसे ही आईआईएमटी कॉलेज पहुंची, छात्र-छात्राएं उनसे मिलने के लिए भारी संख्या में जमा हो गए फिल्म के मुख्य कलाकार मनीत जौरा और गीतांजली सिंह से मिलकर छात्र बेहद प्रसन्न थे। बड़े पर्दे के कलाकार को अपने बीच पाकर छात्र-छात्राओं के चेहरे खिले हुए थे। फिल्मी सितारों के पहुंचने ही



अदाकार मनीत जौरा और गीतांजली सिंह-बाएं

14 सितंबर को फिल्म होगी रिलीज

छात्र-छात्राओं में सितारों के करीब पहुंचने की होड़ लग गई। विचारियों की भीड़ को नियंत्रित करने में विद्यालय प्रशासन को मेहनत करनी पड़ी। फिल्म की अदाकार गीतांजलि ने आईआईएमटी के छात्र-छात्राओं से मिली जबरदस्त समर्थन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम आपके संस्थान में बार-बार आना चाहेंगे। उन्होंने विचारियों से 14 सितंबर को रिलीज होने वाली 'फलसफा'

देखने की अपील की। उनका जबाब देते हुए वह मौजूद विचारियों ने कहा जरूर-जरूर। हम सब देखेंगे। आईआईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक डॉ राहुल गौयल ने फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को एक अचूकी फिल्म बनाने के लिये बधाई दी। आईआईएमटी कॉलेज प्रबंध निदेशक मयंक अग्रवाल ने कॉलेज परिसर में आने के लिए 'फलसफा' के सितारों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे और उनके छात्र 'फलसफा' फिल्म जरूर देखेंगे और आशा करते हैं कि यह फिल्म सुपरहिट होगी।

समलैंगिकता: दुश्मन है जमाना ठेगे से

सुनिधि सिंह, नई दिल्ली

प्रेम एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। नैतिकता अनैतिकता से परे है। हमारे देश में आदमी और औरत के प्रेम पर कड़ा पहरा लगा हुआ है। इश्वर से प्रेम स्वीकार्य है प्रेमी पुरुष हो या महिला। पुरुष अपने आराध्य पुरुष इश्वर से प्रेम करने को स्वतंत्र है, इसी तरह स्त्री किसी भी देवी से, लेकिन देश में रहने वाले पुरुष या स्त्री समलैंगिक प्रेम नहीं कर सकते। समाज इसे मान्यता नहीं देता न ही कानून लम्बी लड़ाई के बाद समलैंगिक रिश्तों के पैरोकार ने समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता दिलाने में सफल हुआ है। 6 सितंबर 2018 को अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आईपीसी की धारा 377 के तहत वास्तविक जीवन में रहने वाले समलैंगिक संबंध को अपराध बताया। धारा 377 को



धारा 377 रद्द किए जाने का स्वागत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में था। इसमें 10 साल या फिर जिंदागी भर जेल की सजा का भी

मनमानी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्तिगत चॉइस को सम्मान देने की बात कही।

प्रवधान था, वो भी गैर-जमानती। यानी अगर कोई भी पुरुष या महिला इस एक्ट के तहत अपराधी साबित होते हैं तो उन्हें बेल देने का कोई प्रावधान नहीं था। समलैंगिकता की इस श्रेणी को एलजीबीटीक्यू (लेसबियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीयर) के नाम से भी जाना जाता है। इस समुदाय के हक के लिए 'नाज फाउंडेशन' काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा था। इस संगठन ने 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय में इसे

लेकर याचिका दायर की थी और अदालत ने समान लिंग के दो वयस्कों के बीच यौन संबंधों को अपराध घोषित करने वाले प्रावधान को 'गैरकानूनी' बताया था। कोर्ट के इस फैसले का जहां समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया है, वहीं बाँलिवुड सिलेब्रिटीज़ ने भी इस फैसले पर अपनी खुशी जताई और ट्रिटर पर अपने रिएक्शन शेर कर दिए। प्रख्याक करण जौहर ने ट्वीट किया, 'ऐतिहासिक फैसला, आज मुझे बहुत गर्व है।' होमोसेक्सुएलिटी को अपराध न मानना और 377 को रद्द करना मानवता और समान अधिकारों की बड़ी जीत है। इस देश को दोबारा सांस लेने का मौका मिला है। वहीं डी सच्चन जो पेशे से एक शिक्षक हैं उनका कहना है कि 'भारत का सामाजिक ढांचा जो है वो अमेरिका और यूरोप जैसा नहीं है इसलिए समलैंगिक कानून आने से समाज में अपराध और बढ़ेंगे।'